वानिकी समाचार

वन विभाग राजस्थान का मासिक पत्र

वर्ष : 26 अंक : 7 जुलाई-2009

पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाओं।
पर्यावरण को प्रदूषण से बचाओ।।

हरित राजस्थान का आगाज़

❐ अभिजीत घोष

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, 18 जून, 2009 को शिक्षा संकुल, जयपुर के परिसर में पौधारोपण कर हरित राजस्थान अभियान का शुभारम्भ करते हुए।

राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से सम्पूर्ण शासन को एकजुट कर हरा–भरा राजस्थान बनाने का संकल्प लिया है, जो राजस्थान जैसे मरू प्रदेश को खुशहाल करने का मंत्र है। राजस्थान एक विषम जलवायु वाला प्रदेश है और आये दिन पड़ने वाले अकाल तथा कम वर्षा की स्थितियां प्रायः बनी ही रहती है। ऐसे हालात में प्रदेश के मुखिया द्वारा पौधारोपण को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन अभियान चलाने का जो संदेश दिया गया है। वह बहुत ही सराहनीय है।

यह सर्वविदित है कि जहां–जहां भी अच्छे वन होते हैं, वहां–वहां वर्षा भी बहुत अधिक होती है। भूमिगत जल भण्डार भरे रहते हैं। तापमान अपेक्षाकृत न्यून बना रहता है और हरियाली के कारण पर्यावरण की शुद्धता भी बनी रहती है। अतः आगामी मानसून में सघन पौधारोपण किये जाने से निःसंदेह कालान्तर में जल संकट से निजात मिल सकेगा। प्रदेश सरकार को जल योजनाओं पर करोड़ों, अरबों रुपया प्रति वर्ष खर्च करना पड़ता है। लेकिन समय पर पूरी वर्षा नहीं होने के कारण जल स्रोत सूखे रह जाते हैं अथवा पर्याप्त जल राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। फलतः अधिकांश जल परियोजनाएं विवादों के घेरे में आ जाती है और जन अपेक्षाओं पर भी खरी नहीं उतरती है। वनों का विस्तार, प्राकृतिक जंगलों का संरक्षण तथा पौधारोपण एक ऐसे विकल्प हैं जो न केवल वर्षा के पानी का संरक्षण कर सकते हैं बल्कि नदियों, जलाशयों, झीलों, बाँधों तथा अन्य सतही जल भण्डारों की जल क्षमता में वृद्धि ला सकते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रदेश को हरा–भरा करने का अभियान केवल पेड़ उगाने का अभियान नहीं है बल्कि वास्तव में प्रकृति प्रदत व्यवस्था के अन्तर्गत जल संरक्षण का भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जिला प्रशासन को पौधारोपण में इस बार सीधा दायित्व सौंपा गया है और नरेगा जैसे राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम से पौधारोपण को जोड़ा गया है। जो एक अभिनव प्रयोग है। इससे सभी सरकारी विभागों की सहभागिता प्राप्त होगी।

शेष पृष्ठ 3 पर.....

सम्पादकीय...

सब मिलकर बनाएं 'हरित राजस्थान'

'हरित राजस्थान' किसी एक की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो राजस्थान की मरू भूमि से जुड़ा हुआ है। सभी को इस कल्पना को साकार करने में अपने-अपने स्तर पर सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए।

जयपुर में शिक्षा संकुल प्रांगण में पौधारोपण कर राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी 'हरित राजस्थान अभियान' का शुभारम्भ करने के बाद भरोसा जताया गया है कि सभी लोग इस पावन उद्देश्य के वाहक बनकर पूरे प्रदेश को एक कड़ी के रूप में जोड़ने में भूमिका निभाएंगे। प्रदेश का कोई भी तबका वंचित न रहे और सभी लोग एक-एक पेड़ अवश्य लगाएं इस भावना को जागृत करने की आज आवश्यकता है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है और कहने मात्र से यह पूरा भी नहीं होगा। सरकार सभी स्तरों पर प्रेरणा का सतत संचरण करने का कार्य करेगी, लेकिन इसकी सफलता के लिए किसान, मजदूर, स्वयंसेवी संगठनों, प्रदेश में कार्यरत सभी सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं सहित प्रदेश के आम अवाम को मन से जुटना होगा। शासन की इच्छा है कि समस्त प्रदेशवासी इस अभिनव शुरूआत के लिए अपने आपको समर्पित करें, पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कामयाबी की ओर बढ़े। यह भी देखना होगा कि वृक्षारोपण के अभियान में शामिल होने वाले मंत्री, नौकरशाह, जनप्रतिनिधि एवं मीडियाकर्मियों सहित सभी लोग समय निकाल कर रोपित पौधों की सार-सम्भाल करें।

प्रदेश में पानी की समस्या विकराल हो रही है। राजस्थान में पानी एक अत्यन्त विरल संसाधन है एवं अपनी अनुपस्थिति से अपना एहसास कराता है। पानी ईश्वर की देन है और गिरते जल स्तर के कारण पानी की समस्या एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है। हरित राजस्थान के इस महाभियान से पर्यावरण संतुलन के साथ अच्छी वर्षा की राह भी प्रशस्त होगी।

राज्य में इस वर्ष ढ़ाई करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें एक लाख किलोमीटर लम्बी सड़कों के किनारे पौधे लगाने के अलावा सरकारी भूमि, वन क्षेत्र, निजी भूमि एवं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में लगाये जायेंगे। वन विभाग अपने स्तर पर एक करोड़ पैतींस लाख पौधे लगायेगा, जबकि शेष उपलब्ध पौधे गैर सरकारी संस्थाओं को उपलबध कराये जायेंगे।

वन्य जीवन

बाघों के हक में वर्ल्ड बैंक की पहल

जंगल कटाई पर रोक, टाइगर रिजर्व की कड़ी सुरक्षा, बाघ मारने पर फांसी, नए जंगल लगाने पर ध्यान होगा तभी जंगल का राजा बच पाएगा। ऐसे समय जब विश्वभर में बाघों की संख्या तेजी से घट रही है, वन कट रहे हैं और धरती पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता ही जा रहा है, वर्ल्ड बैंक द्वारा बाघ बचाने हेतु मदद की घोषणा ठंडी हवा के सुखद झोंके की तरह है। संसार के अत्यंत सुंदर जानवरों में शुमार बाघ का जीवन सिर्फ भारत ही नहीं चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी खतरे में हैं। किसी जमाने में दुनियाँ में एक लाख से ज्यादा बाघ थे। अब 3500 से भी कम रह गए हैं। बाघों के अंगों की बिक्री तिब्बत और चीन में धड़ल्ले से हो रही है। इसके चलते शिकारी बाघ और अन्य वन्यजीवों को क्रूरता से मार रहे हैं। एसईजेड जैसी बड़ी विकास योजनाओं, रेल परियोजनाओं और बांध व रहवासी क्षेत्रों की बढ़ती संख्या की वजह से जंगल कम हो रहे हैं। बेचारा बाघ मुंबई या शंघाई में तो विचरने से रहा। उसे घने जंगल चाहिए, जहां (अ) मानवीय हस्तक्षेप न हो, लेकिन हो, ठीक विपरीत रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप, माफिया का बढ़ता कुप्रभाव, प्रकृति के प्रति आदर में लगातार कमी, वोट की राजनीति से बन रही नीतियों आदि से बेचारा बाघ दहाड़ने के बजाये चुपके से कराह रहा है। उसके अरण्यरूदन को वाशिंगटन में बैठे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जीएलिक ने सुना। उन्होंने स्मिथ सोनियन संस्था के साथ मिलकर दस लाख डॉलर की कार्ययोजना बनाई। भारत में बाघों पर मंडरा रहा संकट काफी गंभीर है। सरिस्का हो या पन्ना, बाघ लगातार मर रहे हैं और सरकार सो रही है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने स्वयं रुचि लेकर बाघ बचाने के लिए एक कार्यदल बनाया था। पर्यावरणविद सुनीता नारायण उसकी अध्यक्ष थीं। कार्यदल की रिपोर्ट पर बाघ संरक्षण प्राधिकरण बना, फिर भी बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है। दो-तीन वर्ष पूर्व नई प्रणाली से की गई बाघों की गिनती से वन विभागों की चिंतायें बढ़ा दी है। जितनी संख्या वन अधिकारी बताते थे, नई और ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से हुई गणना में उतनी संख्या नहीं निकली। इससे संकट की गंभीरता और प्रकाश में आई? आदिवासियों को मिले वन अधिकारों ने बाघ पर आया संकट गहरा दिया है। जंगल कटाई पर कड़ाई से रोक, टाइगर रिजर्व के आसपास कड़ी सुरक्षा, विशेष बजट, बाघ मारने पर फांसी की सजा, नए जंगल लगाने की योजना आदि पर ईमानदारी से और एक साथ काम होगा तो ही जंगल का राजा बच पाएगा। वरना वह भी अगले 10 वर्षों में लुप्त हो जाएगा। बाघ खत्म हुआ तो बचे हुए जंगल भी भारत जैसे देश में खत्म होते देर नहीं लगेगी।

(साभार दैनिक भास्कर)

(पेज 1 का शेष...)

यह भी देखना होगा कि पौधारोपण से पूर्व जनचेतना का कार्य भी हो, स्कूल–कॉलेज के छात्र–छात्राओं को पौधा लगाने से लेकर उनकी बढ़वार किये जाने वाले कार्यों यथा, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटिंग, बाढ़बंदी आदि की जानकारी एंव प्रशिक्षण दिया जावे। जब बड़े पैमाने पर पौधे लगाये जाते हैं तो उचित देखभाल के अभाव में मर सकते हैं। अतः यह भी ध्यान रखना होगा कि रोपित किये गये पौधे जीवित रहे, उनकी समुचित देखभाल हो, उनकी समय–समय पर मोनीटरिंग भी हो। सबका सहयोग ही हरा–भरा राजस्थान बनाने के मार्ग को प्रशस्त करेगा।

सरकार द्वारा नरेगा में इस कार्यक्रम को जोड़ने से वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक इसकी पहुंच होने से जन सहभागिता में भी वृद्धि होगी।

वन विभाग और वनकर्मियों के सामने यह एक चुनौती है। ऐसी चुनौती, जिसमें सबको पौधशालाओं का विस्तर तकनीकी मार्गदर्शन, वनों की सुरक्षा और संरक्षण में अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। सामान्यतः यह माना जाता रहा है कि पेड़ उगाना तथा वनों की सुरक्षा करना केवल वन विभाग का काम है। इसलिए यह कार्य वन विभाग तक ही सीमित रहता आया है। विभाग में एक ओर वित्तीय संसाधनों का अभाव बना रहता है। वहीं दूसरी ओर वनकर्मियों का पर्याप्त संख्या का अभाव भी वन प्रबंधन को प्रभावित करता रहता था। अतः नये परिवेश में व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर काम करने की आवश्यकता है।

स्थानान्तरण/पदस्थापन

राज्य सरकार ने एक आदेश क्रमांक : प. 5 (3) कार्मिक/क–1/2009 जयपुर, दिनांक 06.07.2009 जारी कर श्री ओ.पी. मेहता को अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वाइल्ड लाईफ) जयपुर के पद पर स्थानान्तरित किया है। श्री अम्बरीश चन्द चौबे, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर में श्री ओ.पी. मेहता के स्थान पर तथा वी.एस. राठौड़, उप वन संरक्षक को, उदयपुर (उत्तर) के पद पर पदास्थापित किया गया है।

15 जुलाई से होगा शहरी क्षेत्रों में अभियान

राज्य सरकार ने राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की राजकीय एवं निजी भूमि पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करने के लिए 'हरित राजस्थान योजना' को शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के शहरों में यह योजना 15 जुलाई, 2009 से प्रारंभ होगी। प्रदेश के शहरों में इस योजना को समस्त शहरी निकायों के द्वारा संचालित किया जायेगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए समस्त शहरी निकायों को निर्देश दिये गये हैं।

यह जानकारी देते हुए स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने बताया कि शहरों में वृक्षारोपण के लिए विद्यालय, पार्क, सड़क के किनारे, शहरी निकाय की खाली पड़ी भूमि, कचरागाह स्थानों, अस्पतालों इत्यादि स्थानों का चयन किया जाये। उन्होंने बताया कि चयनित भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए कुल पौधों की आवश्यकता का आंकलन कर वन विभाग, उद्यान व कृषि विभाग एवं निजी पौधशालाओं से पौधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था शहरी निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जाए। हरित राजस्थान योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए चयनित स्थानों पर वृक्षारोपण करने के लिए प्राथमिकता तय करते हुए 15 जुलाई से पूर्व समयबद्ध कार्य योजना तैयार करवाई जायें। इसके लिए शहरी निकाय 15 जुलाई से पूर्व समयबद्ध कार्य योजना तैयार करवाई जाये। इसके लिए शहरी निकाय 15 जुलाई से पूर्व वृक्षारोपण किये जाने वाले स्थानों का चिन्हीकरण कर आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लें।

इसके अलावा पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड, जाली, फेन्सिंग, तार बंदी की व्यवस्था कर ली जाए ताकि वृक्षारोपण के पश्चात पौधों की सुरक्षा हो सकें। वृक्षारोपण करने के उपरांत पौधों की सुरक्षा एवं देखभाल हेतु कीटनाशक, खादी एवं पानी की समुचित व्यवस्था की जायें ताकि पेड़ पौधे हरे–भरे रहें।

इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए निकाय स्तर पर अलग से बजट का प्रावधान किया जाए। योजना के लिए निकाय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। यह नोडल अधिकारी योजना क्रियान्विति के लिए प्रभारी अधिकारी होगा।

शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं, नगर सुधार न्यासों तथा सार्वजनिक ट्रस्टों के पास बहुत अधिक जमीन होती है जिसका उपयोग वे पौधारोपण करने में कर सकते हैं। इससे एक ओर हरित राजस्थान बनाने का लक्ष्य अर्जित किया जा सकेगा तो दूसरी ओर वृक्षारोपण स्थलों से मिलने वाली वन उपज भी प्राप्त होगी जिससे कुटीर उद्योगों तथा वन उपज आधारित कार्यों को भी संचालित करने का मार्ग अग्रसर होगा।

झलकियाँ

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पौधारोपण करते हुए।

शिक्षा संकुल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री।

कृषि मंत्री श्री बुरडक पौधारोपण करते हुए।

पर्यटन मंत्री श्रीमती बीना काक पौधारोपण करते हुए।

फोल्डर का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री एवं वनमंत्री

राज्यमंत्री श्री मालवीय पौधारोपण करते हुए।

पंचायती राज मंत्री श्री भरतसिंह रोपित पौधे को सिंचित करते हुए।

समारोह में उपस्थित जन समुदाय।

पंचायती राज मंत्री श्री भरतसिंह रोपित पौधे को सिंचित करते हुए।

झलकियाँ

राज्यमंत्री, वन एवं पर्यावरण श्री रामलाल जाट पौधारोपण करते हुए।

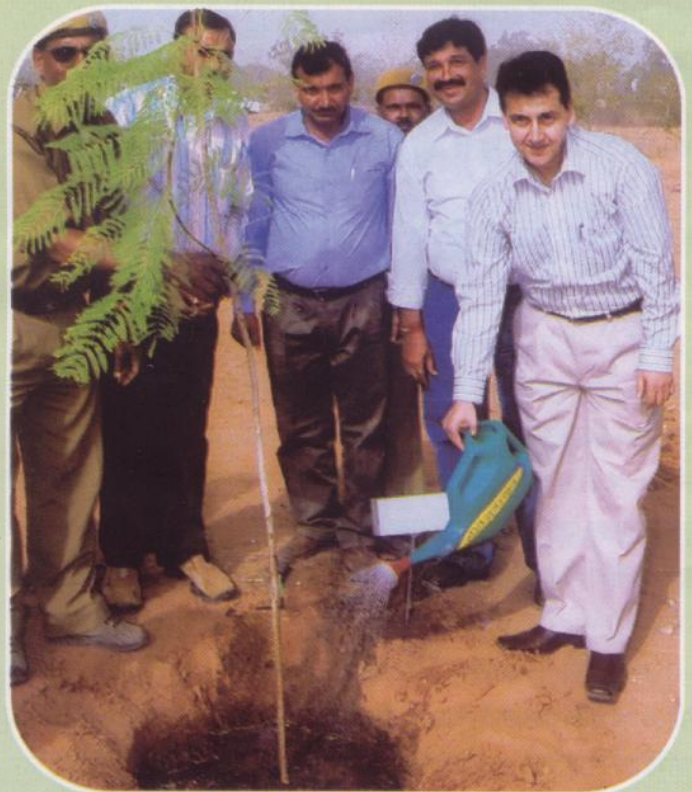

जयपुर विकास आयुक्त, श्री सुधाश पंत पौधारोपण करते हुए।

राज्यमंत्री, श्रीमती गोलमा देवी पौधारोपण करते हुए।

हरित राजस्थान पर

जिला कलेक्टरों एवं वनाधिकारियों की बैठक

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि 'हरित राजस्थान' की परिकल्पना को साकार करने के लिए योजनाबद्ध प्रयासों पर बल दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की अपेक्षा एवं मंशा के अनुरूप कामयाबी की राह प्रशस्त होगी। श्री गहलोत 18 जून, 09 को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित जिला कलक्टर्स कांफ्रेंस के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्ट्रेट, वन विभाग एवं जिला परिषद के अधिकारी पूरी क्षमता, योग्यता, अनुभव, कुशलता और तत्परता का प्रदर्शन करें। अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ जुटें और इस अभियान में बीएसएफ, सेना, आरएसी, सरकारी कार्मिकों और स्वयंसेवी संगठनों सहित आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे देश का 10 प्रतिशत है, इसमें से 70 प्रतिशत भाग पर मरूस्थलीय है और यहां जल की उपलब्धता पूरे देश का मात्र एक प्रतिशत ही है। पानी को लेकर विकट हालात है, इस पर चिंतन मनन करें। जल संरक्षण, बचत और इसके सदुपयोग के लिए प्रेरणास्पद माहौल बनाए। साथ ही प्रदेश में हालात को बदलने के लिए सकारात्मक सोच के साथ सतत् प्रयास करें।

प्रदेश में पिछले 50 सालों से वन क्षेत्र में निरंतर कमी को चिंता का विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने हरा-भरा राजस्थान कैसे बने? ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कैसे हो ? इस पर विचार-विमर्श के लिए लीक से हठकर इस विषय पर कांफ्रेंस का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान में साधनों की कमी नहीं आए इसलिए इसे नरेगा से जोड़ा गया है।

''नरेगा'' के सफल क्रियान्वयन के लिए सामाजिक अंकेक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए गहलोत ने कहा कि इसके लिए अनुकूल माहौल बनाएं। आंध्र प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नरेगा के आरम्भ होने पर वहां राजस्थान के अकाल प्रबंधन के मस्टर रोल व गेट सिस्टम आदि तरीकों को अपनाया गया था, लेकिन अब समानांतर सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को आरम्भ कर वह हमसे आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि आंध्रप्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण के जरिए अनियमितताओं पर निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सामाजिक अंकेक्षण के लिए माहौल का सृजन करने तथा प्रदेश के लोगों के हित में नरेगा की नई गाइड लाईन में यहां की स्थितियों के अनुरूप बिन्दुओं को शामिल करने के लिए सुझाव देने को भी कहा।

चर्चा में आये सुझाव :

- **हरित राजस्थान के लिए योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक : मुख्यमंत्री**
- **स्कूलों में पौधारोपण के लिए संसाधन सुलभ कराए जायें।**
- **आंतरिक मूल्यांकन के पांच नम्बर पेड़ों की सुरक्षा के साथ जोड़े।**
- **पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जुर्माना राशि बढ़ाई जाये।**
- **पौधों की सुरक्षा के लिए मेटेरियल कम्पोनेन्ट बढ़ाएं।**
- **महिलाओं को वन प्रबंधन समिति बनाने का सुझाव।**
- **टिश्यूकल्चर लैब स्थापित कर पौधों की मांग और अंतर को कम किया जाये।**
- **वन क्षेत्र में पत्थर की चारदीवारी बनाने का भी सुझाव आया।**

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ''नरेगा'' में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि सिस्टम में भ्रष्टाचार घर कर गया तो इस योजना का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने नरेगा को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी इसके लिए कठोर कार्रवाई करने में नहीं हिचके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के समय ''नरेगा'' में राजस्थान सबसे आगे है, इसका खूब प्रचार हुआ, लेकिन यह एक सीमा तक ही सफल था। बाद में प्रदेश में नई सरकार बनने पर इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आने लगीं। उन्होंने कहा कि केवल स्कीम को लागू कर दिया जाए और संख्या बल के आधार पर वाहवाही लूटी जाए, यह इसका मकसद नहीं। जरूरतमंद को काम मिले, उन्हें समय पर और पूरा भुगतान हो यह सुनिश्चत होना चाहिए, चाहे संख्या आज जितनी ही क्यों न रहे।

कांफ्रेंस के आरम्भ में मुख्य सचिव श्रीमती कुशलसिंह ने विषय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस महत्वाकांक्षी अभियान से सीधु जुड़े अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) और हरित

राजस्थान को केन्द्र बनाकर यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सम्पन्न कलेक्टर्स सम्मेलन में जिलों की कार्ययोजना की प्रस्तुति के साथ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। जो सराहनीय है।

सम्मेलन के प्रथम सत्र में हरित राजस्थान तथा दूसरे सत्र में नरेगा के सम्बन्ध में चर्चा हुई। जिला कलेक्टरों, मुख्य वन संरक्षक, जिला वन अधिकारियों तथा जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने दोनों कार्यक्रमों को सफल बनाने के उद्देश्य से रचनात्मक सुझाव बताए। इन सुझावों में स्कूलों में पौधारोपण के लिए संसाधन सुलभ कराने तथा आंतरिक मूल्यांकन के पांच नम्बर पेड़ों की सुरक्षा के साथ जोड़ने, पेड़ों की कटाई रोकने हेतु जुर्माना राशि बढ़ाने, पौधों की सुरक्षा के लिए मेटेरियल कम्पोनेन्ट बढ़ाने, महिलाओं को वन प्रबंधक बनाने आदि के सुझाव प्रमुख थे।

जिलों की जलवायु के अनुकूल उपलब्ध स्थानीय प्रजातियों की टिश्यूकल्चर लैब स्थापित कर पौधों की मांग और अंतर को कम करने, बीस सूत्री कार्यक्रम में हुए पौधारोपण की समीक्षा, वन क्षेत्र में पत्थर की चारदीवारी बनाने की अनुमति के सम्बन्ध में भी सुझाव दिये गये।

बैठक में वन अधिकारियों द्वारा नरेगा के एक जाब कार्डधारी को एक हैक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण, निष्क्रिय नर्सरियों को पुनर्जीवित करने, किसानों को नर्सरी लगाने के लिए प्रेरित करने, पेड़ों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान देने, पौधारोपण की जीविकोपार्जन में वृद्धि से जोड़ने, गृहणियों को पौधे उपलब्ध कराने, वर्मी कम्पोस्ट को प्रोत्साहित करने, नहरों के पास खालों में वृक्षारोपण करने, पांच वर्ष तक अधिकारियों के स्थानांतरण नहीं करके उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने, जलाऊ लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग रोकने एवं लोकदेवता के स्थानों की फेंन्सिग करने के सुझाव दिये गये।

वन अधिकारियों द्वारा कांन्फ्रेंस में प्रतिपादित किया गया कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य के 33 प्रतिशत क्षेत्र को वनाच्छादित बनाने के लिए वन विभाग हर संभव प्रयास करेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भरतसिंह ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण संतुलन एवं वनों का संरक्षण वाला क्षेत्र पिछड़ गया है। पहली बार पौधारोपण के लिए इतना बड़ा प्रयास किया गया है इसकी सफलता सभी की भागीदारी से ही संभव है।

उन्होंने बताया कि इस योजना में लगभग एक लाख किलोमीटर लम्बी सड़कों के किनारे पेड़ लगाने का कार्य किया जाएगा। पौधारोपण के बाद पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्रभावी मानीटरिंग एवं देखरेख को भी सुनिश्चित करना होगा।

नरेगा से हरित राजस्थान पर अपने प्रस्तुतिकरण में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के प्रमुख शासन सचिव जी.एस. संधु ने बताया कि गत वर्षों में राज्य में 36 हजार कि.मी. लम्बी सड़कें बनाई गई है। इनके किनारे वन विभाग वन क्षेत्र में वृक्षारोपण करेगा।

उन्होंने बताया कि जुलाई माह से प्रदेश भर में हरित राजस्थान योजना पांच वर्षों के लिए 2013-14 तक लागू की जाएगी। राज्य, जिला एवं पंचायत स्तर पर लागू इस योजना के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजना के क्रियान्वयन की राशि नरेगा के कोष से दी जाएगी।

कलेक्टर्स कान्फ्रेंस के दूसरे सत्र को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सम्मेलन में सभी ने नरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अच्छे सुझाव दिये हैं, जिनका अध्ययन कराया जायेगा। इन सुझावों को राज्य स्तर पर कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर गंभीरता से विचार किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि नये सुझावों को कैसे केन्द्र सरकार को भेजें जिससे वहां से दिशा निर्देशों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य पर परफोरमेंस संख्या के आधार पर नहीं बल्कि गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टरों से कहा कि हमारी परम्पराएं रही हैं कि राज्य में जिला कलेक्टर गांवों में रात्रि विश्राम करें, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ-साथ गांव वालों में भी सुशासन का अच्छा सन्देश जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत नरेगा सहित सभी विभागों के कार्यों की सूची बोर्ड एवं दीवारों पर अंकित की जाये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय ले चुकी है। गांवों में सूची लगी होने पर गांवों में पढ़े-लिखे लोग यह देख सकेंगे कि कौन से काम पर कौन-कौन मजदूर लगे हैं। इससे बेईमानी करने वाले भी सावचेत हो सकेंगे। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि विभिन्न विभागों के कार्यों की सूची बोर्ड पर लगे, यह सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाये। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कार्य स्थलों पर बोर्ड लगवाएं।

बैठक में शिक्षा मंत्री भंवर लाल ने यह सुझाव दिया कि नरेगा के तहत पक्के कार्यों को करवाने के लिए सामग्री के लिए सांसद एवं विधायक कोष से राशि उपलब्ध हो और नकद भुगतान की राशि नरेगा से मिले। सहकारिता मंत्री परसादीलाल मीणा ने नरेगा का पैसा सहकारिता बैंकों में जमा कराने का सुझाव दिया। राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने नरेगा के तहत जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायत समिति को और राज्य स्तर पर सर्वोत्तम जिले को प्रोत्साहन राशि देने का सुझाव दिया।

बैठक में गृहमंत्री शांति कुमार धारीवाल, जनजातीय विकास मंत्री महेन्द्रजित सिंह मालवीय, कृषि मंत्री हरजीराम बुरडक, परिवहन मंत्री बृजकिशोर शर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री बाबूलाल नागर, जन सम्पर्क राज्यमंत्री अशोक बैरवा, कृषि विपणन राज्यमंत्री गुरमीर सिंह कुन्नर, खेल राज्यमंत्री मांगीलाल गरासिया ने भी अपने विचार रखे।

जिला कलेक्टर्स एवं वनाधिकारियों की इस कांन्फ्रेस से यह आशा बलवती हुई है कि वन विभाग के साथ सम्पूर्ण प्रशासन भी इस अभियान में जुड़ जायेगा।

रानीपुरा में समुदाय द्वारा कृष्णमृगों का संरक्षण

❐ महावीर मीणा

टोंक जिले की पंचायत समिति, उनियारा के एक गांव राणीपुरा में स्थानीय समुदाय, विशेषकर मीणा जाति के परिवारों द्वारा कृष्ण मृगों के संरक्षण करने का अद्‌भुत उदाहरण देखने को मिलता है। जानकारी के अनुसार सन् 1962 में रानीपुरा में केवल दो काले हिरण नर व मादा आये थे। इन हिरणों से ग्राम रानीपुरा के मीणाओं ने इतना स्नेह दर्शाया कि इनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होकर सन् 1970 तक इनकी संख्या करीब 500 हो गई और वर्तमान में यह बढ़ते–बढ़ते करीब 1500 हो गई है। मीणा समाज का काले हिरणों के प्रति इस स्नेह को देखकर राज्य सरकार के वन विभाग ने 14 फरवरी, 1984 को रानीपुरा को 'आखेट निषिद्ध क्षेत्र' घोषित कर दिया और शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया और इनकी सुरक्षा का जिम्मा मीणा समाज ने लिया । तब से ही यह समाज इनका पूर्ण संरक्षण कर रहा है और समय– समय पर शिकारियों के साथ मुकाबला करके काले हिरणों के प्राण बचाते रहते हैं।

गत् 6–7 वर्षों से श्री बाबूलाल मीणा की पहल पर मीणा समाज द्वारा काले हिरणों को पूर्ण संरक्षण देने के लिए श्री दादू पर्यावरण समिति नामक संस्था गठित करके इनकी पूर्ण सुरक्षा कर रहे हैं। इसी कार्य से प्रभावित होकर वन विभाग ने जिला स्तर पर संस्था को कई बार सम्मानित किया एवं अनेक एन.जी.ओ. ने भी समाज द्वारा संचालित संस्था को सम्मानित किया। इस कार्य में अपनी जान जोखिम में डालकर मृगों को बचाने वाले कुछ युवक रामप्रसाद मरमट, मोजीराम मीणा, भजन लाल मीणा, घासीलाल आदि ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए हथियारों एवं वाहनों से लैस शिकारियों को पकड़कर पुलिस व वन विभाग को सुपुर्द किया। मीणा समाज काले हिरणों को अपनी फसल व चरी में चरने के लिए मना नहीं करते हैं। वे गर्मी के दिनों में पानी की पूर्ण व्यवस्था करते हैं और रात्रि के समय में पहरा देते हैं ताकि इन काले हिरणों का अस्तित्व बना रहे।

राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, नागौर आदि जिलों में काले हिरणों (कृष्ण मृगों) की सुरक्षा गुरु जम्बोजी के अनुयायी समाज विश्नोईयों द्वारा की जाती है। जिनकी पूरे हिन्दुस्तान में प्रशंसा की जाती है। लेकिन राज्य के टोंक जिले में यह कार्य मीणा समाज के द्वारा किया जा रहा है। कृष्ण मृगों की सुरक्षा ग्राम रानीपुरा में मीणा समाज इस प्रकार कर रहा है कि वहाँ ये मृग फसलों में बेधडक चरते हैं लेकिन कोई इनको खड़ी फसल से नहीं भगाता हैं। इतना ही नहीं, मीणा समुदाय अपने आँखों के सामने इनका शिकार नहीं करने देते हैं।

वर्तमान में मीणा समाज द्वारा संचालित संस्था श्री दादू पर्यावरण संस्थान रानीपुरा द्वारा इनका संरक्षण किया जा रहा है। संस्थान के अध्यक्ष बाबूलाल मीणा ने काले हिरणों के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गर्मी के दिनों में उपरोक्त संस्थान हिरणों के लिए पानी एवं हरे चारे की व्यवस्था जन सहयोग से करवाता है।

अगर कोई शिकारी गाँव में घुसते हैं तो इनको पकड़कर उपरोक्त संस्थान कड़ी सजा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। उनियारा तहसील के करीब 15 गांवों में इस संस्थान ने अपनी कार्य समितियां गठित कर रखी है जो काले हिरणों के संरक्षण में अपना तन, मन एवं धन से हमेशा सहयोग देती हैं। फलतः यह क्षेत्र काले हिरणों का अभयारण्य बन गया है।

अनुरोध :

वानिकी समाचार में प्रकाशनार्थ आलेख, छायाचित्र, विभागीय गतिविधियों की जानकारी, साझा वन प्रबन्ध की सफल कहानियां, कविताएं तथा अन्य सामग्री प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। यह सामग्री ई-मेल से भी भेजी जा सकती है। इस पत्रिका के अंक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

– सम्पादक

Book-Post

वन विभाग, राजस्थान के लिए उप वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, जयपुर से मुद्रित। 2009/3000
संरक्षक : अभिजीत घोष; संपादक : यू.एम. सहाय; सहायक सम्पादक : सूरज जिद्दी Website : www.rajforest.nic.in • E-mail : vanikisamachar@yahoo.co.in